

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 179]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 1974/श्रावण 9, 1896

No. 179]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 1974/SRAVANA 9, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

वित्त मंत्री का भाषण

31 जुलाई, 1974

महोदय,

मैंने जब 1974-75 का नियमित वार्षिक बजट पेश किया था तब से सिर्फ पांच महीने बाद दूसरा फाइनेन्स बिल पेश करना सरकार के लिए कोई आसान फैसला नहीं है। यह एक असाधारण घटना है। और इसका औचित्य यही है कि हमारे सामने एक कठिन आर्थिक परिस्थिति है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मौजूदा हालत में कोई कदम न उठाना वित्तीय गैर-जिम्मेदारी होगी जिससे देश की आर्थिक दशा पर गंभीर असर पड़ेंगे। इसलिए दूसरा फाइनेन्स बिल लाने का फैसला न केवल आर्थिक स्थिति की गंभीरता का संकेत देता है बल्कि इस बात का भी पता चलता है कि सरकार इस गंभीर आर्थिक स्थिति को काबू में कर लेने के लिए कितनी दृढ़ संकल्प है।

2. हम सभी जानते हैं कि मुद्रा-स्फीति पर काबू पाना देश के सामने सबसे महत्वपूर्ण काम है। सरकार ने अब तक जो उपाय मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए अपनाये हैं उनका प्रभाव सीमित रहा है और कीमतें बराबर बढ़ती रही हैं। लोग अनुमान करते हैं कि कीमतें तो लगातार बढ़ती ही रहेंगी, इस तरह सोचने से भी मुद्रा-स्फीति को बढ़ावा मिल रहा है।

3. 1974-75 के केन्द्रीय बजट का उद्देश्य बढ़ते हुए सरकारी खर्च को रोकना, पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त पूंजी जुटाना और घाटे की अर्थव्यवस्था पर निर्भरता को कम करना था। यह मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए अपनायी गयी समूची अर्थ नीति का एक भाग था। अगर पिछले चार पांच महीनों की कीमतों के रुख को देखा जाय तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति का जोर लगभग बना रहा है। जनवरी से मार्च, 1974 तक के तीन महीनों में कीमतें औसत रूप में एक महीने में 2.7 प्रतिशत बढ़ीं। इसकी तुलना में अप्रैल से जून 1974 के तीन महीनों में कीमतों का औसत स्तर 7.8 प्रतिशत बढ़ा जिससे कीमतें औसत रूप में एक महीने में 2.6 प्रतिशत बढ़ीं। कीमतों के मामले में हालत का लगातार गिरते जाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चिन्ता का कारण बना हुआ है।

4. मैं इस समय मुद्रा-स्फीति से लगातार पड़ने वाले दबाव के कारणों के बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहूंगा। इन कारणों के बारे में मैंने अक्सर इस सदन में बहुत कुछ कहा है हालांकि मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि बुनियादी तौर पर इसकी वजह हमारी खेती की पैदावार का कम होना है। हाल की गेहूं की फसल उतनी नहीं हुई जितनी कि हमने पहले आशा लगायी थी। इससे लगता है कि उत्पादकों की सप्लाई को रोकने की प्रवृत्ति को बल मिल गया है। अनाज वसूलने की कीमतों को पर्याप्त रूप से ऊंची करने पर भी अब तक आशा के अनुरूप अनाज वसूला नहीं जा सका है। रबी की फसल में तेलहनों का उत्पादन भी अपर्याप्त रहा और इससे वनस्पति तेलहनों व तेलों के भाव चढ़ते गये। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि जो 1973 में रही थी, पावर की कमी के कारण ठप्प सी रही।

5. इन सभी तत्वों से कुल मांग और पूर्ति के बीच असंतुलन लगातार बना रहा है। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने यह जरूरी समझा कि नये सिरे से एक साथ कई कदम उठाये जायें। हाल ही में जारी किये गये तीन अध्यादेशों में लाभांश दिये जाने पर अस्थायी रोक, मजदूरी व वेतन में होने वाली वृद्धि व अतिरिक्त महंगाई भत्ते को 50 प्रतिशत निष्क्रिय करना और ऊंची आय वाले वर्ग के आय-कर देने वालों द्वारा अनिवार्य जमा शामिल है। इन अध्यादेशों का बुनियादी उद्देश्य यह है कि मांग के दबाव को कम किया जाय और मुद्रा के प्रवाह की दर को रोका जाय। इन उपायों को आंकते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकार के सामने कुछ ही विकल्प थे। मौजूदा परिस्थिति में दूसरा संभव उपाय यही था कि विकास पर किये जाने वाले खर्च में भारी कटौती कर दी जाती लेकिन इससे अर्थव्यवस्था की प्रगति पंगू हो जाती।

6. बैंकों ने हाल के महीनों में भारी मात्रा में ऋण दिये हैं जिससे रिजर्व बैंक को ऋण नियंत्रण और कड़े करने पड़े। हर एक व्यापारी बैंक को हिदायतें दी गई हैं कि वह सबसे बड़े 50 खातों की छानबीन करे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक-ऋण का इस्तेमाल इनवेंटरी को जरूरत से ज्यादा बढ़ाने या अनुत्पादक कामों पर न किया जाय। अभी हाल में 22 जुलाई, 1974 को बैंक-ऋण में 2 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई जिसके साथ साथ व्यापारी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की न्यूनतम ब्याज दर और उन बैंकों में जमा रकमों पर दिए जाने वाले ब्याज की दरों में वृद्धि की गयी। इससे बैंक से ऋण लेकर इनवेंटरी को बढ़ाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा व जमा रकमों का जुटाने में भी सहायता मिलेगी।

7. अभी हाल में हमने जो कदम उठाये हैं वह कदम सही दिशा में उठाये गये हैं। मैं यहां वह स्पष्ट कर दूँ कि इन उपायों से ही कीमतें नहीं चक्की। जो असंतुलन हमारी अर्थ व्यवस्था में है वह बुनियादी तौर से, ख़ती की पैदावार में लगातार वृद्धि ला कर दूर किया जा सकता है, हालांकि ऐसा करना कोई आसान बात नहीं है क्योंकि हमारे देश में उर्वरक का अपर्याप्त उत्पादन हो रहा है और बाहर से मंगाये जाने वाले उर्वरक महंगे हो गये हैं। जो कुछ उर्वरक हमें विदेशों से मिल सकता है, हम खरीद रहे हैं हालांकि इनके आयात का खर्च भारी हो गया है जो 450 करोड़ रुपये तो भी ज्यादा होने की सम्भावना है। 1974-75 के वर्ष की योजना में मूल क्षेत्र के लिए हमने जो पर्याप्त व्यवस्था की है उससे हमें कोयला व इस्पात का उत्पादन काफी बढ़ाने में मदद मिलनी चाहिए। कोयले के उत्पादन और उसको लाने ले जाने में होने वाले सुधार सामने आने लगें हैं। लेकिन मुख्यतः पावर की कमी व यातायात की दिक्कतों के कारण औद्योगिक उत्पादन आमतौर पर अभी अनिश्चित बना हुआ है।

8. सौभाग्य से, हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति सुदृढ़ बनी रही है। इसका मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया गया ऋण, लगातार मिलने वाली विदेशी सहायता और खास-तौर से 1973-74 में हमारे निर्यात से होने वाली आमदनी में तेजी से हुई वृद्धि है। इसके परिणाम-स्वरूप हम अनाज के आयात पर होने वाले खर्च को पूरा कर सके हैं हालांकि हमें काफी दाम देने पड़े हैं। 1974-75 में हमारा निर्यात व्यापार उतना अच्छा नहीं रहा। हमारी विदेश जाने वाली चीजों के दाम हाल के महीनों में घट गये हैं। इसके अलावा कीमतें जिस तेजी से आजकल बढ़ रही हैं उसे देखते हुए हमारी निर्यात की चीजें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में दूसरे देशों की चीजों के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगी जिससे हमारे भुगतान की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इससे पता चलता है कि हमें अपनी कीमतों को बढ़ने से रोकने की कितनी सख्त जरूरत है।

9. इस पृष्ठभूमि में, हमारी अर्थ-व्यवस्था में मांग के दबाव को कम करने के लिए और अधिक उपाय करने की जरूरत अपनेआप स्पष्ट हो जाती है। मुद्रा-स्थिति के मौजूदा दौर में बजट के घाटे की मात्रा को बढ़ने न देना बहुत जरूरी है। और हमने ऐसा करने का दृढ़ निश्चय कर रखा है। अनेक कारणों से हमारे मूल अनुमान गड़बड़ा गये हैं और इससे केन्द्रीय सरकार के बजट का घाटा मूल बजट में अनुमानित 126 करोड़ रुपये की राशि से काफी अधिक हो जाने का खतरा पदा हो गया है। मैं इनमें से कुछ कारणों का यहां जिक्र कर रहा हूँ।

10. जैसा कि सदन को मालम है, सरकार ने हाल में अन्न सम्बन्धी आर्थिक सहायता के बोझ को कम करने के लिए गेहूँ की वसूली की कीमतों में वृद्धि की है। इस समय, सरकार देशी गहूँ और मोटे अनाजों की वसूली के लिए बहुत थोड़ी आर्थिक सहायता देती है। लेकिन पिछले रबी के मौसम में गेहूँ का पर्याप्त उत्पादन न होने और इसकी अपर्याप्त वसूली होने के कारण, जैसा कि मैंने पहले कहा है, सरकार को विदेशों से काफी बड़ी मात्रा में अनाज मंगाना पड़ रहा है, जिससे वह अपनी वितरण प्रणाली को कायम रख सकें। धूँक बाहर से मंगाया जाने वाला गेहूँ देशी गेहूँ से काफी अधिक महंगा पड़ता है लेकिन इसे बेचना उसी कीमत पर पड़ता है, इसलिए अन्न सम्बन्धी आर्थिक सहायता का बोझ 100 करोड़ रुपये के मूल अनुमान से कहीं अधिक हो जाएगा।

11. माननीय सदस्य रेलवे की कमजोर वित्तीय स्थिति से भली भांति परिचित हैं। कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के खर्च का बोझ अधिक होने और हाल की रेलवे हड़ताल के कारण याता-यात में बाधा आने से रेलवे बजट का घाटा 52 करोड़ रुपये की मूल व्यवस्था से काफी अधिक होगा।

12. इसके अलावा, हमें इस तथ्य को भी हिसाब में लेना चाहिए कि कीमतों में लगातार वृद्धि होने से, बजट में अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के लिए की गयी व्यवस्था में भारी वृद्धि करनी पड़ेगी। इसी प्रकार बढ़ती हुई कीमतों और रक्षा कर्मचारियों के वेतन आदि में और अधिक सुधार करने के कारण रक्षा-व्यय में भी कुछ वृद्धि होने की संभावना है।

13. जहाँ तक आयोजना का सम्बन्ध है, कीमतों में लगातार वृद्धि होने से परियोजनाओं की लागत बढ़ गई है और इसके साथ साथ हमारे सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के आन्तरिक साधनों में और कमी हो गई है।

14. आयोजना-परिव्यय और आयोजना-भिन्न परिव्यय को इकट्ठा लेने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि यदि स्थिति में सुधार करने के लिये कुछ कदम न उठाये गये तो उन कारणों से, जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, चालू वर्ष में कुल खर्च और कुल उपलब्ध पूंजी के बीच का अन्तर 126 करोड़ रुपये के उस घाटे से बहुत अधिक होगा, जिसका अनुमान इस वर्ष का बजट पेश करते समय लगाया गया था। हालांकि हमारा खर्च तेजी से बढ़ता जा रहा है लेकिन वर्तमान करों से प्राप्त होने वाला राजस्व से यह संकेत नहीं मिलता कि इस मद से प्राप्त होने वाला राजस्व बजट में अनुमानित राजस्व से कोई खास अधिक होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं सदन में करों के जरिये अतिरिक्त पूंजी जुटाने के प्रस्ताव रखूंगा।

15. लेकिन मैं यह बात कहना चाहूंगा कि घाटा किसी भी तरह केवल नये कर लगा कर पूरा नहीं किया जा सकता और घाटे को कम करने के लिये और भी दूसरे कदम उठाने जरूरी हैं।

16. हम सभी सरकारी खर्चों की पूरे तौर पर जांच-पड़ताल कर रहे हैं जिसे हर सम्भव किफायत की जा सके। यह काम कोई आसान काम नहीं है; क्योंकि इस वर्ष का बजट ऐसी बहुत सी आयोजनागत योजनाओं को जिन्हें स्थगित करने के योग्य समझा गया था छोड़ देने के बाद प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा, यदि चालू परिव्यय में कमी करने का फल यह हो कि मूल क्षेत्र की मुख्य परियोजनाओं को उनके जल्दी पूरा होने के लिये आवश्यक धनराशि प्राप्त होनी बन्द हो जाय, तो किफायत करने का प्रयोजन ही समाप्त हो जायगा जहां तक सम्भव हो, हमें अर्थ-व्यवस्था के मूल क्षेत्रों जैसे बिजली और उर्वरकों में पूंजी लगाने की दर को बनाये रखना है। इसके साथ साथ, हम विकास-भिन्न खर्चों के अलावा कुछ कम प्राथमिकता वाली विकास-योजनाओं के खर्च में भी कमी करने की कोशिश कर रहे हैं हम अपने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और विभागीय उपक्रमों को लाभकारी बनाने की संभावनाओं की भी जांच कर रहे हैं। खर्च में भारी कमी करने का एक अभियान अभी चल ही रहा है। जब तक यह पूरा नहीं हो जाता और हमारे द्वारा किये गये अन्य उपायों के नतीजे सामने नहीं आ जाते तब तक ठीक ठीक यह बताना कठिन होगा कि अन्तिम स्थिति क्या होगी। मुद्रा स्फीति की मौजूदा भीषण स्थिति को देखते हुए हमारा पूरा हरादा है कि केन्द्रीय सरकार के बजट के घाटे को इस वर्ष के बजट में बता गये स्तर तक सीमित रखा जाय और सरकार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सभी आवश्यक कदम उठायेगी।

17. अपने विशिष्ट प्रस्तावों को पेश करने से पहले मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि इन प्रस्तावों के आधारभूत सिद्धान्त क्या हैं। जनसाधारण को भारी कठिनाइयां झेलनी पड़ रहीं हैं, इन कठिनाइयों को देखते हुये आम इस्तेमाल की चीजों पर नये कर लगाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये कर लगाने के लिये वस्तुओं का चुनाव करते समय, मैंने जीवन की बुनियादी आवश्यक वस्तुओं पर नये कर नहीं लगाये हैं। इसके साथ साथ मेरे प्रस्तावों में दिखावे के उद्देश्य से किये जाने वाले खर्च में कमी करने और दुर्लभ माल के इस्तेमाल में अधिकतम किफायत करने की आवश्यकता अन्तर्निहित है। मैंने इस समय कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादकों और व्यापारियों द्वारा कमाये जा रहे छप्परफाड़ मुनाफों की

रकम को, जो अक्सर दिखायी नहीं जाती और जिस पर कर नहीं लगा होता, बढ़ोतरी का प्रयत्न किया है। मुझे यकीन है कि मदन इस बात पर महमत होगा कि मौजूदा स्फीतिकारी स्थिति में उत्पादक की सामान्य आवश्यकताओं से कहीं अधिक इनबैटरी के सामान के संचय करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिये। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने हाल में कुछ उपाय घोषित किये हैं जिनसे बैंक ऋण की लागत में वृद्धि और ऋण को आत्यावश्यक उत्पादन-कार्य की केवल वास्तविक जरूरतों के लिये सीमित करके इस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश की गयी है। मैं आगे जिन कर-प्रस्तावों की रूपरेखा बताऊंगा उनमें से एक का उद्देश्य, रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा-मोर्चे पर की गयी कार्रवाई को पुष्ट करना है इसके साथ साथ पूंजी जुटाने में सहायता देना है जिसकी कि सरकार को जरूरत है।

18. मैं इस अवसर पर राज्य सरकारों पर यह जोर देना चाहूंगा कि राजस्व के मामले में अधिक अनुशासन लाने में उनकी भूमिका केन्द्रिय सरकार से कम महत्वपूर्ण नहीं है। विकास की गति को प्रभावित किये बिना, अपने घाटों को कम करने के लिये राज्य सरकारों को चाहिये कि वे कृषिक करों की क्षमता का पूरा पूरा लाभ उठावें। इसके साथ साथ सिंचाई और बिजली जैसी सेवाओं की दरों का निर्धारण अधिक वास्तविकता के आधार पर करने की अविलम्ब आवश्यकता है। मैं उनसे आग्रहपूर्वक अनुरोध करूंगा कि वे इन दिशाओं में कदम उठावें।

प्रत्यक्ष कर

19. मैं अब अपने कर प्रस्तावों को पेश कर रहा हूँ। पहले यह प्रस्ताव प्रत्यक्ष करों के बारे में है। मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए किये जा रहे हैं उपायों के अन्तर्गत, मैं अनुसूचित बैंकों द्वारा भारत में दिये जाने वाले ऋणों से उनकी ब्याज की जो सकल रकम मिलती है उस पर कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। बैंकों से यह आशा की जाती है कि वह अपनी कार्य प्रणाली को इस कर के अनुरूप ढालेंगे और ऋण लेने वालों से ली जाने वाली ब्याज दरों में जरूरत के मुताबिक घटती बढ़ती कर इस कर की प्रतिपूर्ति कर लेंगे। इस कर से मुद्रा सम्बन्धी व वित्तीय दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इस से ऋण की रकम की लागत बढ़ जायगी और सरकारी राजस्व में और अधिक रकम जायगी। यह कर बैंकों द्वारा लिये गये कुल ब्याज की रकम पर 7 प्रतिशत की दर से लगेगा। इस से बैंकों के लिए गये ऋण की लागत में 1 प्रतिशत की औसत वृद्धि हो जायगी। कर लगाते समय सरकारी सिक्कूरिटियों व स्थानीय निकायों, कम्पनियों और सांविधिक निगमों द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों व दूसरी सिक्कूरिटियों के ब्याज को हिसाब में नहीं लिया जायगा। इसी तरह अनुसूचित बैंकों के बीच होने वाले लेन देन पर लगने वाले ब्याज को इस कर के हिसाब में नहीं लिया जायगा। अनुसूचित बैंकों को पहली अगस्त 1974 के पहले मिलने वाला ब्याज भी इस कर के अन्तर्गत नहीं आयेगा। आयकर अधिनियम के अनुसार कर लगने वाली आय का हिसाब लगाते समय इस कर की रकम की कटौती कर दी जायगी। मैं जल्दी ही इस प्रस्ताव को लागू करने के बारे में अलग से एक बिल पेश करूंगा। इस कर से एक पूरे साल में 60 करोड़ रुपये तक की आमदनी होगी और चालू वर्ष की बाकी अवधि में इससे 25 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

20. स्फीतिकारी स्थिति के परिणामस्वरूप भारी मात्रा में होने वाली अनर्जित आय को ध्यान में रखते हुए मैं पूंजीगत लाभ कर में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। गैर-निगम कर-वाताओं की कर योग्य आय का हिसाब लगाते समय दीर्घ अवधि वाले पूंजीगत लाभ से

कटौती की रकम को, जहाँ इस लाभ का सम्बन्ध भूमि व मकानों से हो, 35 प्रतिशत से घटा कर 25 प्रतिशत किया जा रहा है। अन्य परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण के कारण होने वाले लाभ के मामलों में यह कटौती घटा कर 50 प्रतिशत की जा रही है।

21. दीर्घ अवधि के पूंजीगत लाभ पर कम्पनियों के मामले में कर की मात्रा बढ़ायी जा रही है। यह वृद्धि भूमि व मकानों से मिलने वाले लाभ के मामले में कर की दर को 45 प्रतिशत से बढ़ा कर 55 प्रतिशत करके की जा रही है। ऐसी कम्पनियों के मामलों में जिनमें बहुत ज्यादा लोगों के शेयर हैं और जिनकी कर योग्य आय दीर्घ अवधि वाले पूंजीगत लाभ को छोड़ कर 1 लाख रुपये से अधिक न हो वहाँ 47 प्रतिशत की निचली दर लागू की जायगी। दूसरे तरह की परिसम्पत्ति के हस्तान्तरण के कारण होने वाले पूंजीगत लाभ पर लगाये जाने वाले कर की दर 35 प्रतिशत से बढ़ा कर 45 प्रतिशत की जा रही है। पूंजीगत लाभ से सम्बन्धित व्यवस्थाओं में इन परिवर्तनों से पूरे साल में लगभग 5 करोड़ रुपयों का राजस्व प्राप्त होगा।

अप्रत्यक्ष कर

22. मैं अब प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव पेश कर रहा हूँ। जरूरत के अनुसार पूंजी इकट्ठा करने के लिए मेरे पास कुछ खास खास उत्पादन शुल्कों को बढ़ाने के सिवा दूसरा चारा न था। ऐसा करते समय मेरी यह कोशिश रही है कि जनता के अपेक्षाकृत निर्धन वर्ग पर कम से कम प्रभाव पड़े। मैंने इस बात की भी कोशिश की है कि जिन मर्दों में बिचौलिये आजकल उपभोक्ता व मूल उत्पादक दोनों को नुकसान पहुँचा कर भारी मुनाफा कमा रहे हैं उन मर्दों पर शुल्क की दर बढ़ाई जाय। इन शुल्कों से हमें व्यापार में होने वाले मुनाफों को समेटने में मदद मिलेगी जो इन व्यापारियों को अवांछनीय रूप से प्राप्त हो रहे हैं।

23. इस समय तांबा व तांबा मिश्र धातु और तार की सरियों, तार की छड़ों आदि पर 1500 रुपये प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से उत्पादन शुल्क लगता है। इनसे बनी विशिष्ट चीजों पर 2000 रुपये प्रति मेट्रिक टन की दर से शुल्क लगता है जब कि पाइपों और ट्यूबों पर 10 प्रतिशत मूलानुसार दर लगती है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तांबे की कीमत ऊपर चढ़ती जा रही है। अब तो हमें भी भारी मात्रा में तांबा आयात करना पड़ता है। तांबे के देशी उत्पादक अपनी चीजों को आयात की गई चीजों के दाम पर बेचते हैं और व भारी मुनाफा कमाते हैं क्योंकि उनके उत्पादन की लागत कम होती है। इस आकस्मिक लाभ में से कुछ रकम निकाल लेने के उद्देश्य से मैं तांबे और, उक्त सरियों, छड़ों आदि पर 4000 रुपये प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से बुनियादी उत्पादन शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ; इन की बनी हुई विशिष्ट चीजों पर 4500 रुपये प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से और पाइप व ट्यूब पर 20 प्रतिशत मूलानुसार शुल्क लगाया जा रहा है। शुल्क-दस्त धातु से बनी प्लेटों, चद्दरों, सफिलों, पट्टियों, प्वाइलों या विशिष्ट प्रकार के स्क्रैप से बनी धातु पर 500 रुपये प्रति मेट्रिक टन की दर से लगने वाला मौजूदा शुल्क जारी रहेगा। बगैर कटी छंटी रूप में निकासी की गई चद्दरों व सफिलों के लिए एक निचली दर निर्धारित की गई है। कच्चा तांबा अगर पाइप व ट्यूब बनाने के काम आता हो तो उस पर अब किये गये शुल्क को मुजरा करने की व्यवस्था भी जारी रहेगी। इन प्रस्तावों से मैं आशा करता हूँ कि 8.40 करोड़ रुपयों तक का राजस्व प्राप्त होगा जिसमें बड़े हुए सहायक शुल्क के फलस्वरूप जिसका निर्धारण प्रभावी बुनियादी शुल्क के प्रतिशतांश के रूप में होता है, मिलने वाला राजस्व भी शामिल है।

24. ऐसी ही बातों को ध्यान में रखते हुए मैं बिनपिटे जस्ते पर बुनियादी शुल्क को 500 रुपये प्रति मेट्रिक टन से बढ़ा कर 1500 रुपये कर देने का प्रस्ताव कर रहा हूँ, इस धातु से बने विशिष्ट माल पर इस शुल्क को 800 रुपये प्रति मेट्रिक टन से बढ़ा कर 1800 रुपये और पाइपों व ट्यूबों पर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव कर रहा हूँ। जस्ते की प्लेटें, चद्दें, सर्किलें, पट्टियों और शुल्क दिये हुए जस्ते की बनी पवाइलों पर 300 रुपये प्रति टन के हिसाब से शुल्क जारी रहेगा। इससे 5.07 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा जिसमें सहायक शुल्कों से प्राप्त होने वाली रकम भी शामिल है। बुनियादी उत्पादन शुल्क में इस समय प्रस्तावित वृद्धि करने के परिणामस्वरूप आयात किये गये ताबे और जस्ते पर कोई अतिरिक्त प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगेगा।

25. रियन व सिंथेटिक रेशों व धागों की कीमत बढ़ जाने से इस पर लगे शुल्क का, जो मात्रा-नुसार लगता है, भार कम हो गया है। इसलिए मैं नायलान के रेशों से बने धागों और स्टेपल रेशे वाले धागों और सैन्डलोज के रेशों से बने धागों के बारे में मात्रानुसार शुल्कों की दरों को उपयुक्त रूप से बढ़ा देने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे 11.38 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व आयेगा। मछली पकड़ने के जाल व पैराशूट की रस्सियों के बनाने में काम आने वाले नायलान के धागे पर मौजूदा रियायती दर जारी रहेगी। मैं इस वृद्धि के लिए एसिटेड के धागे को भी छोड़ रहा हूँ।

26. कम्पोजिट मिलों और बिजली से चलने वाले करघों द्वारा मैन्यूफैक्चर किये गये कपड़ों पर धागे के स्तर पर लगने वाले शुल्क के अन्तर को कम करने के लिए मैं उस सूती धागे पर मात्रानुसार शुल्क की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ जो बिजली से चलने वाले करघों द्वारा सुपरफाइन, फाइन व मीडियम-ग्रे कपड़े तैयार करने के काम आता है। ये बड़ी हुई दरें इसी काउंट के सूत पर भी लागू होंगी जो हीजरी के धागे, सिलाई के धागे आदि बनाने में इस्तेमाल होता है। सीधी रीलों पर चढ़े लच्छी के सूत पर, जिसका इस्तेमाल हथकरघों द्वारा किया जाता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन वृद्धियों से 9.70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। माननीय सदस्यों को यह जान कर खुशी होगी कि निचले काउंट वर्गों के सूत को, जिसका उपयोग सामान्यतः मीडियम-ग्रे और मोटे कपड़े के बनाने के लिए किया जाता है, अछूता छोड़ा जा रहा है।

27. उत्पादन में बाधाओं के कारण टायरों की सप्लाई में कमी हो गई है और व्यापारियों द्वारा कुछ किस्मों के टायरों पर भारी मुनाफा लिया जा रहा है। इस मुनाफे को बटोरने और राजस्व जुटाने के एक उपाय के रूप में, मैं स्कूटरों, मोटर साइकिलों और मोपेडों के टायरों को छोड़ कर, जिन पर मौजूदा रियायती दर पर ही शुल्क लगता रहेगा टायरों के मूल्यानुसार शुल्क में 5 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे 8.8 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। लेकिन साइकिलों के टायरों और ट्यूबों और पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों में इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से बनाये जाने वाले टायरों को पूरी तरह छूट प्राप्त होती रहेगी।

28. माननीय सदस्यों को सीमेंट की आम कमी और व्यापारियों द्वारा कमाये जाने वाले छप्परफाड़ मुनाफों की जानकारी तो होगी ही। इन मुनाफों से कम से कम कुछ अंश को समे टने और अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए, मैं सीमेंट के बुनियादी शुल्क को 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 30 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूँ। सहायक शुल्क की प्राप्ति में होने वाली आनुषंगिक वृद्धि सहित, इस प्रस्ताव से राजस्व में 29.37 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी।

29. सिगरेटों पर बुनियादी उत्पादन शुल्क की मौजूदा टैरिफ दर 200 प्रतिशत मूल्यानुसार है। एक अधिसूचना द्वारा, 10 रुपये प्रति हजार तक की कीमत वाले सिगरेटों के मामले में यह बुनियादी शुल्क 75 प्रतिशत मूल्यानुसार निर्धारित किया गया है। 10 रुपये प्रति हजार से अधिक कीमत वाले सिगरेटों के मामले में, 10 रुपये प्रति हजार से ऊपर के प्रत्येक अतिरिक्त रुपये अथवा उसके किसी भाग के लिए, इस शुल्क में 3 प्रतिशत मूल्यानुसार की वृद्धि कर दी जानी है। राजस्व प्राप्ति के उपाय के रूप में, मैं बुनियादी बिल्टु पर (अर्थात् उन सिगरेटों पर जिनकी कीमत 10 रुपये प्रति हजार से अधिक नहीं है) बुनियादी शुल्क की दर को 75 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ा कर 85 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूँ। लेकिन 10 रुपये प्रति हजार की कीमत से ऊपर के प्रत्येक अतिरिक्त रुपये अथवा उसके किसी भाग के लिए शुल्क में होने वाली वृद्धि की 3 प्रतिशत मूल्यानुसार दर बनी रहेगी।

30. चूंकि 200 प्रतिशत मूल्यानुसार की उच्चतम सीमा अधिक कीमती ब्रांड वाले सिगरेटों के शुल्क को सीमित कर देती है, इसलिए मैं इस सीमा को बढ़ा कर, 250 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी करता हूँ। मुझे आशा है कि भाग्यवन्तों को, जो अधिक मंहगे ब्रांड के सिगरेटों को खर्च उठा सकते हैं, यह जान कर गौरव होगा कि अब वे सरकारी खजाने में अधिक योगदान देंगे। सिगरेटों के बारे में मेरे प्रस्तावों से 16.45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, जिसमें सहायक शुल्क के रूप में ज्यादा मिलने वाली रकम भी शामिल है।

31. मैं ठलवां लोहे, लेटेक्स फोम स्पंज, एस्बेस्टस सीमेंट की बनी चीजों और बिजली के बल्बों तथा बिजली की फ्लोरोसेंट ट्यूबों के सम्बन्ध में बुनियादी शुल्कों में वृद्धि करने का प्रस्ताव भी करता हूँ। इनसे कुल मिला कर 8.14 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

32. केवल केन्द्र के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाने के उपाय के रूप में, मैं स्टील इगाट और लोहे या इस्पात से बनी चीजों पर सहायक शुल्क की दरों को प्रभावी बुनियादी शुल्क के 75 प्रतिशत से बढ़ा कर 100 प्रतिशत करने, और स्केल्प, टिन प्लेटों और टीन की चाबरों के सहायक शुल्क की दरों को प्रभावी बुनियादी शुल्क के 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 70 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। किन्तु रेल मार्गों पर इस्तेमाल की जाने वाली रेल पटरियों और स्लीपर छड़ों पर यह वृद्धि लागू नहीं होगी। इन प्रस्तावों से देश में बने माल की कीमतें बाहर से मंगायी जाने वाली वसी ही वस्तुओं के भत्ते के अनुरूप हो जायेंगी। इससे 26.85 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व जुटाने में भी सहायता मिलेगी। ये संशोधित सहायक शुल्क अब तक की तरह केवल देश में उत्पादित वस्तुओं पर लागू होंगे और इनके कारण आयात की गई वस्तुओं पर अधिक ऊँची दरों से प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क नहीं लगेंगे।

33. कुछ खास किस्मों के सूती कपड़े पर जैसे सूटिंग, गैवरडीन, फर्निशिंग, ब्लेण्डेड, एम्ब्रा-इडरी वाले, इम्प्रेग्नेटेड अथवा कोटेड कपड़े पर मैं पहली दफा प्रभावी बुनियादी शुल्क के 33½ प्रतिशत की दर से प्रभावी सहायक शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ; इससे 6 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

34. फरवरी, 1974 में प्रस्तुत मेरे बजट-प्रस्तावों के भाग के रूप में कागज और गत्ते की विभिन्न किस्मों पर लगने वाले भातानुसार शुल्कों की दरों पर पुनर्विचार किया गया था और उनमें

वृद्धि की गई थी। इस बीच कागज और गत्ते की अधिकांश किस्मों की कीमतों में कागज उद्योग द्वारा भारी वृद्धि कर दिये जाने से मौजूदा माद्वानुसार शुल्कों का मल्यानुसार भार प्रतिशतांश के रूप में काफी कम हो गया है। इसलिए मैं विभिन्न किस्मों के कागज और गत्ते के शुल्क में वर्ष में दूसरी बार वृद्धि करने के लिए मजबूर हो गया हूँ। तदनुसार मैं कागज और गत्ते की सभी किस्मों के प्रभावी बुनियादी शुल्क की $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत की दर से सहायक शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। अधिक ग्राम किस्मों के छपाई और लिखने के कागज को, जिसका वजन 65 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से अधिक न हो, और जिसका इस्तेमाल कार्डों, पाठ्य पुस्तकों आदि के लिए किया जाता है और जिसका कर-निर्धारण इस समय 15 पैसे प्रति किलोग्राम की मौजूदा दर से किया जाता है, प्रस्तावित सहायक शुल्क से विशेष रूप से छूट दी जा रही है। अखबारी कागज और हाथ से बने कागज और गत्ते पर भी शुल्क नहीं लगेगा। इस प्रस्ताव से 13.20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

35. प्लास्टिक की देशी व विदेशी चीजों के मूल्य के बीच के अन्तर को कम करने के लिए मैं सहायक शुल्क की दर को प्रभावी बुनियादी शुल्क के 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 40 प्रतिशत कर देने का और इस प्रकार 9 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व जुटाने का प्रस्ताव करता हूँ। लेकिन जब प्लास्टिक का आयात किया जायेगा तो अब तक की तरह उसे प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क से, सहायक उत्पादन शुल्क के बराबर की छूट मिलती रहेगी।

36. मैं पेंट्स और वर्निश के सहायक शुल्क को प्रभावी बुनियादी उत्पादन शुल्क के $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर देने का भी प्रस्ताव करता हूँ जिससे 1.80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

37. अभी हाल तक डी एम टी और केप्रोलेक्टम का आयात विदेशों से ऊंची अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर किया जा रहा था। इस बीच देश के अन्दर डी एम टी का उत्पादन शुरू हो गया है और केप्रोलेक्टम कारखाने में जल्दी ही उत्पादन शुरू हो जाने की संभावना है। उन कीमतों को देखते हुए जिन पर इन वस्तुओं का आयात विदेशों से किया जाता था और राजस्व के उपाय के रूप में मैं, पहली बार केप्रोलेक्टम पर 50 प्रतिशत की दर से और डी एम टी पर 25 प्रतिशत की दर से मूल्यानुसार शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। अनुमान है कि इससे 12.40 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। लेकिन विदेशों से आयात किये जाने वाले केप्रोलेक्टम और डी एम टी पर प्रस्तावित शुल्कों के परिणामस्वरूप, प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क नहीं लगेगा।

38. उत्पादन शुल्कों से सम्बन्धित प्रस्तावों से पूरे वर्ष में 166 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, जिसमें से लगभग 20 करोड़ रुपये राज्यों और 146 करोड़ रुपये केन्द्र को मिलेगा।

सीमा-शुल्क

39. मैंने फरवरी, 1974 के अपने बजट भाषण में अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि की जिन प्रवृत्तियों का जिक्र किया था, वे अब भी बनी हुई हैं। इन परिस्थितियों में, मैंने मुख्य सीमा शुल्कों में परिवर्तन न करने का निश्चय किया है, हालांकि केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में प्रस्तावित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप प्रतिसन्तुलनकारी शुल्कों से 1 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त राजस्व के प्राप्त होने का अनुमान है।

40. जिन मामलों में अधिसूचनाएं जारी कर 1 अगस्त, 1974 से परिवर्तन लागू करने का प्रस्ताव है, उन मामलों से सम्बन्धित अधिसूचनाओं की प्रतियां मैं यथासमय सभा पटल पर रखूंगा ।

41. सीमा शुल्कों और केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों दोनों को मिला कर, केन्द्र को पूरे वर्ष में 147 करोड़ रुपये अथवा चालू वित्तीय वर्ष के शेष भाग में लगभग 98 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, जिसमें राज्यों का हिस्सा शामिल नहीं है ।

42. ऊपर मैंने जिन विभिन्न कर प्रस्तावों की रूपरेखा दी है उनसे केन्द्र को पूरे वर्ष में लगभग 210 करोड़ रुपये और 1974-75 में 123 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा । राज्यों को भी इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप पूरे वर्ष में लगभग 22 करोड़ रुपये और चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 13 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे ।

43. जैसा कि मैंने पहले कहा है, दूसरा फाइनेंस बिल पेश करना कोई मामूली घटना नहीं है । मौजूदा स्थितिकी आर्थिक मजबूरियों के कारण हमारे पास कोई अन्य वास्तविक सक्षम विकल्प नहीं बचे हैं । मैं चाहता हूँ कि सदन द्वारा ये प्रस्ताव इसी परिप्रेक्ष्य में देखे व परखे जाने चाहिए ।

Speech of Minister of Finance 31st July, 1974

Sir,

The presentation of a second Finance Bill only five months after I presented the regular annual budget for 1974-75 has not been an easy decision for the Government. It is an event of unusual significance and derives its justification from the fact that we are faced with a difficult economic situation. I am, however, convinced that not to act in the present situation would amount to fiscal irresponsibility, with serious consequences for the economic health of the country. Thus the decision to come forward with a second Finance Bill is not only an indication of the seriousness of the economic situation, but also a measure of the Government's determination to grapple with it effectively.

2. It is self-evident that controlling inflation is today the single most important task facing the country. The measures adopted so far by the Government to curb inflation have had a limited impact and the upward pressure on prices has persisted. There is a general expectation of continued price increases, which itself has constituted an inflationary factor.

3. The thrust of the Central Budget for 1974-75 was to restrain the growth of Government expenditure, mobilise additional resources on a substantial scale, and to reduce reliance on deficit financing. This was part of the overall anti-inflationary strategy. However, judging by price trends in the last four or five months, there has been no visible reduction in the strength of inflationary forces operating in the economy. Over the three months April to June, 1974, the rise

In the general price level was of the order of 7.8 per cent, yielding an average monthly increase of about 2.6 per cent, as compared to an average monthly increase of 2.7 per cent during the three months January to March, 1974. This continuing deterioration on the price front has been a source of the greatest concern to Government.

4. I do not wish to dwell at length on the causes for the persistence of inflationary pressures. I have talked about these often enough in this House. I would venture to say that these are basically rooted in the sluggishness of agricultural production. The recent wheat crop has not been up to original expectations. As a result, the tendency on the part of producers to hold back supplies seems to have strengthened. Despite a very sizable increase in procurement prices, procurement so far has fallen short of expectations. The production of oilseeds in the rabi season has also been inadequate, and this has strengthened bullish sentiment in the markets in regard to vegetable oilseeds and oils. Industrial production which remained virtually stagnant in 1973 continues to be inhibited by shortages of power.

5. All these factors point to the persistence of a sizable imbalance between aggregate demand and supply. As a result, Government have considered it necessary to come forward with a fresh package of measures designed to reduce the imbalance. The basic objective of the three recent Ordinances, involving temporarily restrictions on declaration of dividends, immobilisation of 50 per cent of additional Dearness Allowances and of increase in wages and salaries, and compulsory deposits by income tax payers in higher income groups, is to reduce the pressure of demand and decelerate the rate of growth of money supply. In any appraisal of these measures, we must not lose sight of the narrow options open to the Government. In the present situation, the only other feasible course of action would be a drastic cut in all developmental expenditure. This would entail severe adverse effects on the future growth of the economy.

6. A large expansion in bank credit in recent months has led the Reserve Bank to tighten further its credit controls. Instructions have been issued to each commercial bank to scrutinise the top 50 accounts in order to ensure that bank credit is not used for excessive accumulation of inventories or diverted for non-productive purposes. More recently, an increase of 2 per cent in the Bank rate, accompanied by an increase in both the minimum lending rate and in deposit rates of commercial banks, announced on July 22, 1974, will help to reduce further the incentive to accumulate inventories with the help of bank credit; it will also facilitate mobilisation of deposits.

7. The measures that we have recently adopted are steps in the right direction. Let me be clear: by themselves they cannot stabilise prices. Fundamentally, the imbalances that now exist in our economy can be removed only through a sustained increase in agricultural production, though this is not going to be an easy task because of inadequate indigenous production of fertilizer and steep increases in their import prices. We are purchasing as much fertilizer abroad as we can in spite of the formidable nature of the import bill which is likely to be over Rs. 450 crores. The ample provision that we have made for the core sector in the annual plan for 1974-75 should also enable us to secure a significant increase in the production of coal and steel. Improvements in the production and transport of coal are already visible. Mainly because of power shortages and transport difficulties, the overall outlook for industrial production is however uncertain.

8. Fortunately, our foreign exchange reserves have held up fairly well. This is due mainly to borrowings from the International Monetary Fund, continuity of external assistance, and particularly to a rapid growth in our export earnings during 1973-74. As a result we have been able to finance sizable imports of food-grains though at very considerable cost. The export outlook for 1974-75 is however not equally encouraging. The prices of some of our export products have declined in recent months. In addition, the high current rate of inflation constitutes a serious threat to the maintenance of the competitiveness of our exports, which may threaten the viability of our balance of payments. This only underlines the pressing need to control our rate of inflation.

9. Against this background, the need for further measures to reduce the pressure of demand in our economy is self-evident. In the present inflationary environment, it is essential to contain the size of the budgetary deficit. This we are determined to do. However, a number of factors have upset our original calculations and are threatening to push up the Central Government's budgetary deficit well beyond the original budgeted figure of Rs. 126 crores. Let me mention some of these.

10. As the House is aware, Government have recently increased the issue prices of wheat in order to scale down the burden of the food subsidy. Currently, there is only a small element of subsidy in the procurement of indigenous wheat and coarse grains. However, an account of unsatisfactory production and inadequate procurement of wheat during the last rabi season, the Government is having to import, as I mentioned earlier, sizable quantities of foodgrains in order to maintain the public distribution system. As imported wheat costs much more than indigenous wheat but has to be sold at the same price, the burden of the food subsidy will be much higher than the original provision of Rs. 100 crores.

11. The weak financial position of the railways is well known to the Honourable Members. Because of the higher burden of pay and allowances of the staff and the disruption of traffic caused by the recent railway strike, the deficit in the railway budget will increase substantially beyond the original provision of Rs. 52 crores.

12. Additionally, we, must reckon with the fact that by reason of the continuing increase in prices, the budgetary provision for additional dearness allowance will have to be substantially increased. There is also likely to be some increase in expenditure on defence because of rising costs and further improvements in the emoluments of defence personnel.

13. On the Plan side, the continued increase in prices had led to an escalation of project costs accompanied by a further erosion in the internal resources of some of our public sector enterprises.

14. Taking both Plan and non-Plan outlays together, it seems clear for reasons I have just mentioned that unless a number of remedial steps are taken, the gap, between aggregate expenditure and the total resources in sight in the current year will be very much larger than the deficit of Rs. 126 crores which was estimated when presenting this year's budget. While expenditures have been going up sharply the trend of yields from taxes at their present levels does not suggest that there will be any substantial excess over the estimate of revenue made in the budget. It is in this context that I have come before this House with proposals for mobilising additional resources by way of taxation.

15. I should like to say, however, that the potential deficit can by no means be covered by fresh taxation only, and that there is clearly need to take other complementary steps to reduce the deficit.

16. We have undertaken a comprehensive review of all Government expenditure, in a search for possible economies. This is not an easy task because this year's budget was framed after eliminating many Plan schemes which were considered postponable. Moreover, it would be a self-defeating exercise if a reduction in current outlays were to result in key projects in the core sector being refused the funds necessary for their early completion. To the maximum extent possible we have to maintain the rate of investment in such core sectors of the economy as power and fertilizers. At the same time, we are seeking to effect economies not only in all non-developmental expenditure, but also on development schemes which have a somewhat lower priority. We are also exploring the possibilities of increasing the profitability of our public sector enterprises and departmental undertakings. An exercise to cut expenditure drastically is now under way. Until this has been completed and the results of other measures taken by us are known, it would be difficult to indicate precisely what the final position would be. In view of the acute inflationary situation prevailing we fully intend to contain the Central Government's budget deficit to the level indicated in this year's Budget and Government will take all necessary steps to this end.

17. Before I unfold my specific proposals, I would like to explain to the House the rationale underlying these proposals. In the background of the great hardships being endured by the common man, there is clearly no case for imposing fresh levies on articles of mass consumption. Accordingly in my choice of commodities for taxation, I have avoided imposition of new taxes on the basic necessities of life. At the same time the need to discourage conspicuous consumption and to effect maximum economy in the use of scarce materials is implicit in my proposals. In addition, I have made an attempt to mop up the windfall gains currently being made by producers and middlemen in certain sensitive commodities, often in the form of undeclared and untaxed profits. I am sure the House will agree with me that in the present inflationary situation, accumulation of inventories far in excess of normal requirements of production, must be discouraged. Some of the recent measures announced by the Reserve Bank of India

seek to achieve this objective by raising the cost of bank credit, and by restricting credit only for the genuine needs of essential production. One of the fiscal proposals I shall outline in a few moments seeks to complement the action already taken by the Reserve Bank on the monetary front, while at the same time helping in raising resources needed by the Government.

18. I would like to take this opportunity to impress upon State Governments that they have no less a vital role than the Central Government in contributing to greater fiscal discipline. In order to reduce their deficits without affecting the pace of development, they ought to exploit fully the potential offered by agricultural taxation. At the same time, there is urgent need for a more realistic pricing of services like irrigation and electricity. I would strongly urge them to take steps in these directions.

DIRECT TAXES

19. I shall now explain my tax proposals, dealing first with proposals in the field of direct taxes. As a part of the anti-inflationary package, I propose to levy a tax on the gross amount of interest received by scheduled banks on loans and advances made in India. The banks would be expected to adjust their functioning to this tax and reimburse themselves to the extent necessary by making appropriate adjustments in interest rates charged from borrowers. The proposed tax will have both a monetary and a fiscal impact in that it will serve the purpose both of raising the cost of borrowed funds and of supplementing Government revenues. The proposed tax will be levied at the rate of 7 per cent of the gross amount of interest earned by the banks. This would imply on an average an increase of about 1 per cent in the cost of borrowings from the banks. Interest on Government securities, as also debentures and other securities issued by local authorities, companies, and statutory corporations will not be included in the tax base. Interest received on transactions between scheduled banks will likewise be exempted from the proposed levy. Interest accruing to scheduled banks before 1st August, 1974 will be outside the ambit of the proposed measure. The proposed tax will be allowed as deduction in computing taxable income under the Income-tax Act. I propose to introduce a separate Bill shortly to give effect to the proposal. The yield from this measure will be of the order of Rs. 60 crores in a full year. For the remaining part of the current year, however, the revenue will be about Rs. 25 crores.

20. In view of large unearned incomes accruing as a result of the inflationary situation, I propose to increase the tax on capital gains. The deduction from long-term capital gains allowed in computing the taxable income of non-corporate taxpayers is being reduced from 35 per cent to 25 per cent where such gains relate to lands and buildings. In respect of gains arising from transfer of other assets, the deduction is being reduced from 50 per cent to 40 per cent.

21. The incidence of tax on long-term capital gains is also being increased in the case of companies. This increase is being brought about by raising the rate of tax from 45 per cent to 55 per cent in respect of gains relating to lands and buildings. A lower rate of 47 per cent will be applied in the case of widely held companies whose taxable income, excluding long-term capital gains, does not exceed Rs. 1 lakh. The rate of tax applicable on capital gains arising from the transfer of other assets is being raised from 35 per cent to 45 per cent in the case of all companies. These alterations in the provisions relating to the capital gains tax will yield about Rs. 5 crores in a full year.

INDIRECT TAXES

22. I now come to my proposals relating to indirect taxes. In order to raise the needed resources, I have no option but to increase Central Excise duties selectively. In doing so, it has been my endeavour to keep to the minimum the impact on the poorer sections of the community. I have also tried to raise duties on those items, where the middleman is today retaining a large margin, to the detriment of both the consumer and the primary producer. These duties will help to mop up unintended gains accruing to the trade.

23. At present copper and copper alloys in crude form and wire bars, wire rods, etc., carry a basic excise duty of Rs. 1500.00 per metric tonne. Specified manufactures of these carry a rate of Rs. 2000.00 per metric tonne while pipes and tubes are assessable at 10 per cent *ad valorem*. The international prices of copper

have been soaring. Even now the bulk of our requirements have to be imported. The indigenous producers of copper have also been selling their products at prices on par with the prices of imported goods, and thus enjoy a substantial benefit as their own cost of production is lower. To siphon off a part of this fortuitous profit, I propose to increase the basic excise duty on copper in crude form and on wire bars, wire rods, etc., to Rs. 4000.00 per metric tonne; on specified manufactures of these to Rs. 4500.00 per metric tonne; and on pipes and tubes to 20 per cent *ad valorem*. The existing provisions for collection of duty at the rate of Rs. 500.00 per metric tonne on plates, sheets, circles, strips and foils made out of duty-paid metal, or metal made out of specified types of scrap will continue. A lower rate has also been fixed for sheets and circles cleared in untrimmed condition. The provisions for set-off of duty-paid on copper in crude form if used for the manufacture of copper pipes and tubes will also continue. Through these proposals, I expect to secure additional revenue to the extent of Rs. 8.40 crores, inclusive of the consequential accrual of increased auxiliary duty, which is determined as a percentage of the effective basic duty.

24. On similar considerations, I propose to increase the basic duty on unwrought zinc from Rs. 500.00 to Rs. 1500.00 per metric tonne; on specified manufactures of this from Rs. 800.00 to Rs. 1800.00 per metric tonne, and on pipes and tubes from 10 per cent to 20 per cent of *ad valorem*. Zinc plates, sheets, circles, strips and foils made, out of duty-paid unwrought zinc, or specified types of scrap, or their combination, will continue to pay duty at Rs. 300.00 per tonne. The additional revenue accrual from this will be Rs. 5.07 crores, inclusive of the auxiliary duty component. Imports of copper and zinc will not, however, be liable to any additional countervailing duty as a result of the increases now proposed on the basic excise duties.

25. With the rise in prices of rayon and synthetic fibres and yarn, the incidence of duty, based on specific rates, has gone down. I, therefore, propose to step up suitably the specific rates in respect of nylon filament yarn and staple fibre and filament yarn of cellulosic origin. The will provide an additional revenue of Rs. 11.38 crores. The concessional rate available to nylon yarn for use in the manufacture of fishing nets and parachute cords will, however, continue. I am also not bringing acetate yarn within the purview of these increases.

26. With the objective of reducing the gap in the incidence of the duty at the yarn stage on fabrics manufactured by the composite mills and the powerloom units, I propose to raise the specific rates of duty on cotton yarn normally going into the manufacture of superfine, fine and medium-A fabrics manufactured by powerlooms. The increased rates will also apply to yarn of corresponding counts used in the manufacture of hosiery, sewing thread etc. Hank yarn in straight reels used by handlooms will remain unaffected. These changes will thus provide some stimulus to the handloom industry. These increases will yield an additional revenue of 9.70 crores. Honourable Members will be happy to know that yarn of lower count groups normally used in the manufacture of medium-B and coarse fabrics is being left untouched.

27. Due to production constraints, shortages have developed in the availability of tyres, and on certain categories high premia are being charged by the middleman. As a mopping-up measure, and to raise revenue, I propose to step up by 5 per cent the *ad valorem* duty on tyres, other than those meant for scooters, motor cycles and mopeds, which will continue to carry the present concessional rate. This will yield an additional revenue of Rs. 8.8 crores. Tyres and tubes for cycles, and tyres specially designed for use in animal-drawn vehicles will, however, continue to be wholly exempted.

28. Honourable Members are aware of the general scarcity of cement, and the windfall gains being reaped by the dealers. To absorb at least a part of these gains and to raise additional revenue, I propose to increase the basic duty on cement from 25 per cent to 30 per cent *ad valorem*. Inclusive of the consequential increase in accruals from the auxiliary duty, this proposal will add Rs. 29.37 crores to the revenues.

29. The present tariff rate of basic excise duty on cigarettes is 200 per cent *ad valorem*. By a notification, basic duty has been prescribed at 75 per cent *ad valorem*, if the value of the cigarettes does not exceed Rs. 10.00 per thousand. In respect of cigarettes having a value higher than Rs. 10.00 per thousand, this duty is increased by 3 per cent *ad valorem* for every additional rupee or part thereof in excess of Rs. 10.00 per thousand. As a revenue measure, I propose to

raise the rate of basic duty at the base point (i.e. cigarettes of which the value does not exceed Rs. 10.00 per thousand) from 75 per cent *ad valorem* to 85 per cent *ad valorem*. The incremental rate of 3 per cent *ad valorem* for every additional rupee or part thereof in excess of the value of Rs. 10.00 per thousand will, however, continue.

30. As the ceiling of 200 per cent *ad valorem* restricts the duty on the more expensive brands, I also propose to raise this to 250 per cent *ad valorem*. I would hope those fortunate enough to afford the more costly brands will feel more virtuous in the knowledge that they will now be contributing in larger measure to the exchequer. The additional revenue from my proposals relating to cigarettes will amount to Rs. 18.45 crores, inclusive of the increased accrual by way of auxiliary duty.

31. I also propose to raise the basic duties in respect of pig iron, latex foam sponge, asbestos cement products and electric lighting bulbs and fluorescent lighting tubes. These will together yield an additional revenue of Rs. 8.14 crores.

32. As a measure for raising additional revenue exclusively for the Centre, I propose to step up the rates of auxiliary duty on steel ingots, and iron or steel products, from 75 per cent to 100 per cent of the effective basic duty, and that on skelp, tin plates and tinned sheets from 50 per cent to 70 per cent of the effective basic duty. Rails and sleeper bars used for railway track will not, however, attract the increase. These proposals, while bringing the indigenous prices more in tune with the imported prices of comparable products, will also help to raise an additional revenue of Rs. 26.85 crores. These revised auxiliary duties will as hitherto apply only to indigenous production, and not result in higher countervailing duty on imports.

33. On certain varieties of cotton fabrics like suiting, gaberdine, furnishings, blended, embroidered, and impregnated or coated fabrics, I propose for the first time an effective levy of an auxiliary duty of excise at the rate of 33-1/3 per cent of the effective basic duty; this will yield an additional revenue of Rs. 6.0 crores.

34. The specific rates of duties on various categories of paper and paper board were reviewed and stepped up as a part of my budget proposals presented in February, 1974. Since then the steep increases in the prices of most varieties of paper and board effected by the industry have brought down considerably, in percentage terms, the *ad valorem* incidence of the existing specific duties. I am, therefore, constrained to step up the duty on various categories of paper and paper board for the second time this year. I accordingly propose to levy an auxiliary duty at the rate of 33-1/3 per cent of the effective basic duty on all varieties of paper and paper board. Commoner varieties of printing and writing paper, not exceeding 65 grammes per square metre, used for exercise books, text books, etc. and assessed at present at a concessional rate of 15 paise per kilogram are being specifically exempted from the proposed auxiliary duty. Newsprint and hand-made paper and board will also not be affected. This measure will result in an additional revenue of Rs. 13.20 crores.

35. In an effort to narrow the gap between the indigenous and imported prices of plastics, I propose to increase the auxiliary duty of excise from 20 per cent to 40 per cent of the effective basic duty, and thus raise an additional revenue of Rs. 9 crores. However, plastics when imported will as hitherto continue to be exempt from the countervailing duty, equal to the auxiliary duty of excise.

36. I also propose to increase the auxiliary duty on paints and varnishes from 33-1/3 per cent to 50 per cent of the effective basic excise duty, which will bring an additional revenue of Rs. 1.80 crores.

37. Till recently DMT and caprolactam were being imported at high international prices. The indigenous production of DMT has since started while the caprolactam unit is expected to go into production shortly. Having regard to the prices at which these products were imported and as a revenue measure, I propose to levy a duty for the first time at the rate of 50 per cent *ad valorem* on caprolactam and 25 per cent *ad valorem* on DMT. This is expected to yield a revenue of Rs. 12.40 crores. The proposed levies will not result in countervailing duties on the imported caprolactam and DMT.

38. The proposals relating to excise duties will lead to a gain in revenue of about Rs. 166 crores in a full year, of which about Rs. 20 crores will accrue to the States and Rs. 146 crores to the Centre.

Customs Duties

39. The inflationary trends in international prices to which I had referred in my budget speech in February, 1974 continue. In these circumstances, I have decided to leave unchanged customs duties proper, though additional revenue to the extent of Rs. 1 crore is expected from countervailing duties consequent on the changes proposed in Central excise duties.

40. Where changes are proposed to be effected by issue of notifications effective from the 1st August, 1974, I shall in due course lay copies of such notifications on the Table of the House.

41. Taking Customs and Central Excise duties together and exclusive of States' share, the additional revenue accruing to the Centre will be of the order of Rs. 147 crores in a full year or Rs. 98 crores approximately for the rest of the current financial year.

42. The various tax proposals that I have outlined will yield a revenue of approximately Rs. 210 crores in a full year and Rs. 123 crores in 1974-75 for the Centre. The States will also receive Rs. 22 crores approximately in a full year and Rs. 13 crores approximately during the current year, as a result of these proposals.

43. As I stated earlier, the presentation of a Second Finance Bill is not an ordinary event. The economic compulsions of the current situation do not leave us with any really viable alternatives. It is in this perspective I would wish the House to view and to judge these proposals.